दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, सोमवार 24 जनवरी 2022 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 118

महत्वपूर्ण एवं खास

दिल्ली में 1995 के बाद जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश हुई

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में इस साल जनवरी में अब तक 69.8 मिमी बारिश हुई है। इससे पहले 1995 के पहले महीने में शहर में इतनी बारिश हुई थी। आंकड़ों के अनुसार, 1950 के बाद से, दिल्ली में 1989 में जनवरी में 79.7 मिमी बारिश हुई थी, उसके बाद 1995 में इस महीने के बराबर बारिश हुई थी। शनिवार को हुई बारिश के बाद शहर का अधिकतम तापमान गिरकर 14.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में व्यापक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 100 फीसदी दर्ज की गई।

पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिये वर्ष 2022 और 2021 के पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार नवाचार, सामाजिक सेवा,शैक्षिक योग्यता, खेल, कला एवं संस्कृति और बहादुरी जैसी छह श्रेणियों में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए पीएमआरबीपी पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष, बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 29 बच्चों को पीएमआरबीपी-2022 के लिए चुना गया है। पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेते हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। नकद पुरस्कार पीएमआरबीपी 2022 विजेताओं के खातों में अंतरित किये जायेंगे।

30 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात करेंगे पीएम मोदी

नईदिल्ली (आरएनएस)। पीएम मोदी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद 'मन की बात' कार्यक्रम की 85वीं कड़ी को सुबह 11:30 बजे संबोधित करेंगे। सामान्यतः यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होता है लेकिन गांधी पुण्यतिथि के कारण साल का पहला संस्करण अपने निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को ट्वीट किया, इस महीने की मन की बात, जो 30 तारीख को होगी, गांधी जी को उनकी पुण्य तिथि पर स्मरण करने के बाद सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। मन की बात प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो कार्यक्रम है जो हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार और मोबाइल एप पर भी किया जाता है।

जल जीवन मिशन की झांकी 13 हजार फीट की ऊंचाई पर जल आपूर्ति प्रदर्शित करेगी

नईदिल्ली (आरएनएस)। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर जलशक्ति मंत्रालय की झांकी प्रदर्शित करेगी कि कैसे लद्दाख में 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जल जीवन मिशन लोगों के घरों में स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। सरकार के अनुसार, जल जीवन मिशन देश के सबसे कठिन इलाकों में उन समुदायों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है, जो जलवायु की गंभीरता और पीने के पानी की कमी का सामना करते हैं, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात में ऊंचाई पर या रेगिस्तान में। विशेष रूप से, जल जीवन मिशन की झांकी को 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। लद्दाख क्षेत्र में, सर्दियों में दिन के दौरान अधिकतम तापमान शून्य से नीचे रहता है और रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।

सरकार ने 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की

नईदिल्ली (आरएनएस)। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर तथा संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के रूप में संस्थान को 51 लाख रुपये नकद तथा एक प्रमाण पत्र एवं व्यक्तिगत स्तर पर 5 लाख रुपये नकद तथा एक प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।

इस वर्ष के पुरस्कार के लिए 1 जुलाई, 2021 से नामांकन आमंत्रित किये गए थे। वर्ष 2022 के पुरस्कार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था। पुरस्कार योजना के अंतर्गत संस्थाओं और व्यक्तियों से 243 वैध नामांकन प्राप्त हुए।

वर्ष 2022 के लिए, (1) गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (संस्थान श्रेणी) और (2) प्रोफेसर विनोद शर्मा (व्यक्तिगत श्रेणी) को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। .

गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (जीआईडीएम) 2012 में स्थापित गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, गुजरात के आपदा जोखिम को कम-से-कम करने संबंधी (डीआरआर) क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। रणनीतिक रूप से डिज़ाइन किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से, जीआईडीएम ने महामारी के दौरान बहु-संकट जोखिम प्रबंधन और इसे कम करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर 12,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। हाल के कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं ङ्क उपयोगकर्ता-अनुकूल गुजरात अग्नि सुरक्षा अनुपालन पोर्टल का विकास और एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के पूरक के रूप में कोविड-19 निगरानी प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत कोविड -19 सिंड्रोम निगरानी (एसीएसवाईएस) प्रणाली का विकास आदि।

प्रोफेसर विनोद शर्मा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक संयोजक हैं, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आपदा जोखिम को कम-से-कम करने (डीआरआर) से सम्बंधित विषय को राष्ट्रीय एजेंडा के प्रमुख कार्य के रूप में शामिल करने की दिशा में अथक प्रयास किये हैं। भारत में डीआरआर में उनके अग्रणी कार्य ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) तथा अन्य सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) में आपदा प्रबंधन विषय के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में, उन्होंने जलवायु परिवर्तन और डीआरआर को जोड़ने के लिए पंचायत स्तर की तैयारी योजनाओं की शुरुआत करते हुए सिक्किम को डीआरआर लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है।

भारत, अमेरिका के विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने पर चर्चा की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत और अमेरिका के विशेषज्ञों ने शनिवार को कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न तकनीकों पर चर्चा करते हुए कहा कि वे 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से पांच - जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ताकत, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, खपत और उत्पादन जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी की है।

विज्ञान विभाग के सचिव एस.चंद्रशेखर ने कहा, सख्त जलवायु व्यवस्था के तहत हम उत्सर्जन कटौती प्रौद्योगिकियों के पोर्टफोलियो के सही संतुलन की पहचान और अपनाने का एहसास कर सकते हैं। ग्लासगो में हाल ही में संपन्न सीओपी-26 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ-साथ महत्वाकांक्षाओं को सामने लाया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद हम जलवायु लक्ष्यों को पूरा करेंगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्बन कैप्चर पर पहली कार्यशाला में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, पीएम ने हम सभी को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनने को कहा है। उन्होंने सीसीयूएस के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आरडी एंड डी की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की हालिया पहलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएसटी सीसीयूएस के क्षेत्र में सहयोगी आरडी एंड डी के लिए अमेरिका सहित अन्य सदस्य देशों के साथ मिशन इनोवेशन एंड एक्सेलेरेटिंग सीसीयूएस टेक्नोलॉजीज (एसीटी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय प्लेटफार्मों का हिस्सा बन गया है।

दिल्ली और वाराणसी के बीच 'दिव्य काशी यात्रा' ट्रेन चलाई जाएगी

नईदिल्ली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ''दिव्य काशी यात्रा'' ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बताया था कि दिव्य काशी यात्रा के लिए एक विशेष ट्रेन दिल्ली से शुरू होने जा रही है। आईआरसीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी आनंद झा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को चलाए जाने के संबंध में शुक्रवार को घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती मांग के मद्देनजर 'दिव्य काशी यात्रा' ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका वाणिज्यिक संचालन दिल्ली से काशी के लिए 22 मार्च से होगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन में प्रथम और द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में कुल 156 सीट होंगी। उन्होंने बताया कि आईआरसीटीसी यात्रियों के लिये चार रात और पांच दिन का यात्रा पैकेज उपलब्ध कराएगा, जिसमें खाना, रहना और वाराणसी के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर घूमना शामिल है।

कश्मीर में ताजा बर्फबारी से जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद

श्रीनगर (आरएनएस)। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में रविवार को ताजा बर्फबारी हुई जबकि अन्य इलाकों में बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह घाटी के कई इलाकों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। वहीं ताजा हिमपात-बारिश की वजह से श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग बंद हो गया है और खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी धाम के लिए परिचालित हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घाटी के कई इलाकों में खासतौर पर दक्षिण इलाके में रात के दौरान फिर हिमपात हुआ। अधिकारियों के मुताबिक घाटी के प्रवेश द्वारा माने जाने वाले दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड और नजदीकी कोकरनाग में करीब छह इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अनंतनाग में भी तीन इंच बर्फ गिरी है।

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां, पुलवामा और कुलगाम जिलों में भी दो से सात इंच तक बर्फ गिरी है।

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम में भी दो इंच बर्फ गिरी है। उन्होंने बताया कि घाटी के उत्तरी इलाकों में भी ताजा बर्फबारी हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने कर्मचारियों और मशीनों को सड़कों से बर्फ हटाने के काम पर लगाया है।

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर सहित घाटी के अन्य इलाकों में बारिश होने की खबर है, लेकिन इसकी वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे से परिचालित उड़ानें प्रभावित नहीं हुई हैं क्योंकि दृश्यता करीब 1000 मीटर है।

उन्होंने बताया कि घाटी के अधिकतर इलाकों में शनिवार रात को न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आई है।

सरकार देश में कृषि प्रबंधन में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत में गुणवत्तापूर्ण खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल करते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को किफायती बनाने के दिशानिर्देश जारी किए। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें कृषि ड्रोन की लागत का 100 प्रतिशत तक या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, के अनुदान की कल्पना की गई थी। यह धनराशि कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके तहत किसानों के खेतों में बड़े स्तर पर इस तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा।

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75 फीसदी तक अनुदान पाने के लिए पात्र होंगे। उन कार्यान्वयन एजेंसियों को 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आकस्मिक व्यय उपलब्ध कराया जाएगा, जो ड्रोन खरीदने की इच्छुक नहीं हैं लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हाई-टेक हब्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्ट-अप्स से किराये पर लेना चाहते हैं। उन कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आकस्मिक व्यय 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित रहेगा, जो ड्रोन के प्रदर्शन के लिए ड्रोन खरीदना चाहते हैं। वित्तीय सहायता और अनुदान 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध होगा।

ड्रोन के उपयोग के माध्यम से कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के क्रम में, मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन और उससे जुड़े सामानों की 40 प्रतिशत मूल लागत या 4 लाख रुपये, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना किसान सहकारी समितियों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा की जाती है। वहीं एसएमएएम, आरकेवीवाई या अन्य योजनाओं से वित्तीय सहायता के साथ किसान सहकारी समितियों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए सीएचसी या हाई-टेक हब्स की परियोजनाओं में ड्रोन को भी अन्य कृषि मशीनों के साथ एक मशीन के रूप में शामिल किया जा सकता है।

कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर रहे कृषि स्नातक ड्रोन और उससे जुड़े सामानों की मूल लागत का 50 प्रतिशत हासिल करने या ड्रोन खरीद के लिए 5 लाख रुपये तक अनुदान समर्थन लेने के पात्र होंगे। ग्रामीण उद्यमियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या उसके समान परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए; और उनके पास नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निर्दिष्ट संस्थान या किसी अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थान से दूरस्थ पायलट लाइसेंस होना चाहिए।

राज्यों को अब तक एक सौ 61 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराये गये

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।

देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 161.47 करोड़ से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।

भारत दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत ने अप्रैल-अक्टूबर (2020-21) के दौरान 114 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया है।

भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात का 200 मिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर लिया है, इसे खीरे के अचार बनाने के तौर पर वैश्विक स्तर पर गेरकिंस या कॉर्निचन्स के रूप में जाना जाता है।

2020-21 में, भारत ने 223 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के साथ 2,23,515 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया था।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने बुनियादी ढांचे के विकास, वैश्विक बाजार में उत्पाद को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के पालन में कई पहल की हैं।

खीरे को दो श्रेणियों ककड़ी और खीरे के तहत निर्यात किया जाता है जिन्हें सिरका या एसिटिक एसिड के माध्यम से तैयार और संरक्षित किया जाता है, ककड़ी और खीरे को अनंतिम रूप से संरक्षित किया जाता है।

खीरे की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात की शुरूआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में एक छोटे से स्तर के साथ हुई थी और बाद में इसका शुभारंभ पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हुआ। विश्व की खीरा आवश्यकता का लगभग 15त्न उत्पादन भारत में होता है।

खीरे को वर्तमान में 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें प्रमुख गंतव्य उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देश और महासागरीय देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस, चीन, श्रीलंका और इजराइल हैं।

अपनी निर्यात क्षमता के अलावा, खीरा उद्योग ग्रामीण रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में, अनुबंध खेती के तहत लगभग 90,000 छोटे और सीमांत किसानों द्वारा 65,000 एकड़ के वार्षिक उत्पादन क्षेत्र के साथ खीरे की खेती की जाती है।

प्रसंस्कृत खीरे को औद्योगिक कच्चे माल के रूप में और खाने के लिए तैयार करके जारों में थोक में निर्यात किया जाता है। थोक उत्पादन के मामले में एक उच्च प्रतिशत का अभी भी खीरा बाजार पर कब्जा है। भारत में ड्रम और रेडी-टू-ईट उपभोक्ता पैक में खीरा का उत्पादन और निर्यात करने वाली लगभग 51 प्रमुख कंपनियां हैं।

एपीडा ने प्रसंस्कृत सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

औसतन, एक खीरा किसान प्रति फसल 4 मीट्रिक टन प्रति एकड़ का उत्पादन करता है और 40,000 रुपये की शुद्ध आय के साथ लगभग 80,000 रुपये कमाता है। खीरे में 90 दिन की फसल होती है और किसान वार्षिक रूप से दो फसल लेते हैं। विदेशी खरीदारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं।